बिहार के लिये विकास पैकेज

3110. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा बिहार विकास पैकेज की घोषणा की गई थी जिसके अंतर्गत बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तार करना, बरौनी में पैट्रोकैमिकल काम्प्लैक्स का निर्माण करना, हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन का बिहार तक विस्तार करना और अशोक पेपर मिल का पुनर्वास करना इत्यादि कार्यों को अविलम्ब पूरा किया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजनाएं अब भी केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित हैं ;

(ग) क्या सरकार उक्त योजनाओं को लागू करके स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की महत्वकांक्षाओं को पूरा करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व० श्री राजीव गांधी ने 15-6-1989 को पटना में अपने भाषण में बिहार में कई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मांगों के उत्तर में इन परियोजनाओं पर चर्चा की ।

(ख) से (घ) प्रत्येक परियोजना के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

(1) **बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तार** पूर्वोत्तर से कच्चे तेल की कम आपूर्ति के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाने की अप्रयुक्त शोधन क्षमता रही है । बरौनी तेल शोधक कारखाने को यथा संभव अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं । बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की आपूर्ति बढाने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा हल्दिया से बरौनी को आयातित कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक नई कच्चा तेल पाइप लाइन बिछाने हेतु एक सभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(2) **बरौनी में पेट्रो-रसायन परिसर** का निर्माण-बरौनी में एटोमैटिक परिसर के लिए कोई योजना/प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा है ।

(3) **बिहार एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन का विस्तार**

बिहार के लिए एच० बी० जे० पाइप लाइन के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है । प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और पहले की गई वचनबाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए एच० बी० जे० पाइप लाइन के साथ और अधिक आंबंटन पर विचार करना व्यावहारिक नहीं है ।

(4) **अशोक पेपर मिल का पुनर्वास**--

अशोक पेपर मिल, रामेश्वर नगर, बिहार को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देना केन्द्र सरकार के लिए संभव नहीं है । बिहार सरकार को सलाह दी गई है कि वे इस मामले को बी० आई० एफ० आर० को भेजने के लिए विचार करें ताकि उपयुक्त पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जा सके । राज्य सरकार किसी निजी उद्यमी को मिल को हस्तांरित करने और उसका प्रबंध संभालने के लिए आमंत्रित करने की संभावना पर भी विचार कर सकती है । इस बीच अशोक पेपर मिल कामगार यूनियन ने मिल का प्रबंध अपने हाथ में लेने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है । मामला न्यायाधीन है ।

Hike in prices of Maruti car

3147. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of Maruti Jeeps, vans and cars have of late been increased despite the Biggest duty cuts granted in 1993-94 Budget for the automobile industry, if so, the increases effected during the current year; and

(b) what are the reasons for the price-hikes?